

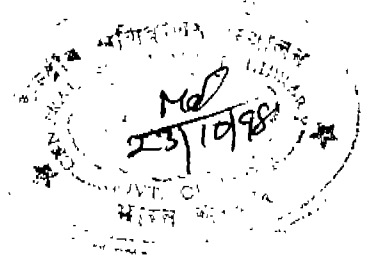


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 160 ]  
No. 160]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1998/श्रावण 3, 1920  
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1998/SHRAVANA 3, 1920

योजना आयोग

संकल्प

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1998

सं. आई टी-टी एफ/5/98.—भारत सरकार ने यह महसूस किया है कि 80 के शतक के मध्य में देश ने सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति हासिल की परन्तु फिर भी वह संभावित प्रगति बहुत ही कम है इसलिए भारत को सूचना क्रान्ति के दौर में और विश्व-स्तरीय सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक सुपर पावर बनाने व उसे अग्रणी बनाने का संकल्प किया है। भारत सरकार सूचना-प्रौद्योगिकी को मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को परिवर्तित करने वाले एक कारक के रूप में मानती है जिससे 21 वीं शताब्दी में एक ज्ञान आधारित समाज पैदा होगा। इस दिशा में, प्रथम चरण के रूप में भारत के लिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करने और गत्यावरोधों को दूर करने के लिए वर्तमान नीति और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित परिशोधन व परिवर्तन किए गए हैं :

- (1) प्रधानमंत्री कार्यालय की दिनांक 22-5-1998 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 360/31/सी/10/98-ई एस-II के अनुसार सूचना-प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना-प्रौद्योगिकी कार्य-योग्यता की 108 संस्तुतियां, जो परिशिष्ट में दी गयी हैं, उन्हें भारत सरकार के सभी संबद्ध मंत्रालय/विभाग अधिसूचित करें और पद्धति-प्रक्रिया/विधि से संबंधित अनुदेश एवं संशोधन शीघ्र ही संस्तुतियों की भावना को प्रतिबिम्बित करते हुए जारी किये जायें।
- (2) अल्पावधि में भारतवर्ष को एक इंफोटेक सुपर पावर बनाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रेरणास्पद मिशन को प्राप्त करने की दिशा में सभी अवसरनात्मक अवसरों को हटाने के लिए और राष्ट्रव्यापी सूचना-प्रौद्योगिकी संस्कृति के निर्माण हेतु एक प्रभावी जागरूकता अभियान शुरू किया जायेगा।

न. शेषगिरि, विशेष सचिव

## परिशिष्ट

1. दूर-संचार विभाग द्वारा इंटरनेट अधिगम नोड खोले जाएंगे और 26 जनवरी, 2000 तक सभी जिला मुख्यालय और प्राधिकृत स्थानीय प्रभार-क्षेत्रों में आई एस पी केन्द्रों को खोला जाएगा । अंतरिम उपाय के रूप में और जब तक कि नोड सभी स्थानीय प्रभार क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं कराये जाते तब तक इंटरनेट के समीप जाने के लिए अधिगम नोड 15 अगस्त, 1998 से स्थानीय कॉल दरों पर शीघ्रता से उपलब्ध कराये जाएंगे । यह सुनिश्चित करने के लिए आई एस पी जिम्मेदार होगा कि टेलीफोन ट्रैफिक के लिए इस सुविधा का दुरुपयोग न हो ।
2. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर विकास और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए कार्ययोजित या पट्टे पर दिये गए परिपथों (सर्किटों) के आधार पर वॉयस व डॉटा कम्युनिकेशन की अनुमति दी गई है, परन्तु कोई भी टेलीफोन ट्रैफिक की अनुमति नहीं दी गयी है । वॉयस व डॉटा अनुप्रयोगों के लिए उच्च क्षमता रखने वाले सर्किटों और 64 के बी पी एस पर अधिभार को 15 अगस्त, 1998 से वापिस लिया जायेगा ।
3. क्लोज प्रयोक्ता दल (सी यू जी), मूल सेवा के अनुज्ञप्तिधारी, सेल्यूलर सेवा और अन्य मूल्य आधारित सेवा और प्रयोक्ताओं द्वारा उच्च गति के लीज पर लिए गए डॉटा सर्किटों के लिए दूर-संचार विभाग द्वारा वसूल किये गये दुगुने लीज-किराया प्रभारों में से एक तरफ के सामान्य लीज किराया प्रभारों को कम कर दिया जायेगा ।
4. बैडविथ जारी करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी) या निजी क्षेत्र के एस टी पी या सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धनात्मक संगठनों द्वारा किए गए अनुरोध पर प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर इंस्टलमेंट की सूचना देते हुए बी एस एन एल द्वारा कार्रवाई की जायेगी । भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क एस टी पी आई और सरकारी नेटवर्क सेवा प्रदायकों को इंस्टलमेंट तक सीधे ही अपनी बैण्ड विल्ट अपेक्षाओं को भेजने के लिए उन्हें डाइरेक्ट एक्सेस प्रोवाइडर कटेगोरी-111 का दर्जा दिया जायेगा ।
5. सूचना प्रौद्योगिकी सेवा संभरकों द्वारा केन्द्रीय कॉल केन्द्रों का गठन करने की अनुमति दी जायेगी, जिसके लिए दूर संचार विभाग और अन्य मूल टेलीकॉम सेवा संभरक बैडविथ उपलब्ध करायेगे ।

6. दूर संचार विभाग द्वारा कुछ नगरों में 31 दिसम्बर, 1998 तक आसूचना नेटवर्क (आई एन) जिसमें निशुल्क फोन सुविधा और प्रीमियम सेवाएं (अर्थात् 1-800 और 1-900 सेवा) शामिल हैं, शुरू की जायेगी ।

कंपनियों द्वारा आई एस पी ऑपरेशनों का गठन करने के लिए पहले पांच वर्षों में कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जायेगा और पांच वर्षों के बाद एक रुपया का नाममात्र लाइसेंस शुल्क वसूल किया जायेगा ।

8. इंटरनेट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे पर वी एस एन एल पर एकाधिकार की सुविधा को वापिस लिया जायेगा और प्राधिकृत सार्वजनिक/सरकारी संगठनों को वी एस एन एल गेटवे के कार्यकलापों को पूरा किए बिना इंटरनेट गेटवे अधिगम सुविधा को सीधे ही उपलब्ध कराने की अनुमति दी जायेगी । निजी आई एस पी को सुरक्षा संबंधी अनुमति प्राप्त करने के बाद ऐसे गेटवे को उपलब्ध कराने की अनुमति दी गयी है ।

8. जिसके लिए प्राइवेट आई एस पी केन्द्रों का इंटरफेस केवल डॉट के साथ होगा जोकि विविध सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा संबंधी निपटान की प्राप्ति के लिए एक प्रक्रिया संबंधी प्रणाली तैयार की जायेगी ।

9. रेलवे, राज्य विद्युत बोर्डों और राष्ट्रीय ताप शिड निगम को बेसिक और मूल्य आधारित सेवाओं के लिए डॉट के लाइसेंसियों या डॉट को ज्यादा/अतिरिक्त डॉटा लीज आधार पर सम्प्रेषित करने के लिए या जहाँ कहीं भी लागू हो वहाँ लाइसेंस की शर्तों के साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों को लेते हुए अन्य उपभोक्ताओं को यह निशुल्क प्राप्त होगी ।

10. डॉट डॉटा संप्रेषण के लिए गार्वनमेट डॉटा नेटवर्क्स और क्लोस्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क्स की आंतरिक कनेक्टिविटी को अनुमति देगा । अन्य नेटवर्कों के लिए डॉट और कार्यदल द्वारा इंटर कनेक्टिविटी नीति एक महीने के अन्दर तैयार की जायेगी ।

11. किसी भी सेवा संभरक को अतिरिक्त लाइसेंस की अनुमति प्रदान किए बिना प्राधिकृत केबल टी वी के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी जायेगी । परन्तु यह लागू होने वाली केबल नियमों पर निर्भर होगा ।

12. "लास्ट माइल" लिंकेंज की सूचना-प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग उद्यमों, सूचना-प्रौद्योगिकी संवर्धनात्मक संगठनों और आई एस पी के लिए फाइबर ओपटिक्स या रेडियो कम्यूनिकेशन द्वारा निर्बाध रूप से अनुमति दी जायेगी । रेडियो लिंकेंज की स्थिति में, बारम्बार हस्तक्षेप करने से बचने के लिए वायरलेस सलाहकार द्वारा दिए जाने वाले समन्वय का अनुसरण किया जायेगा ।
13. नॉन इंटरफेरेंस प्रकार के वायर लैस उपस्कर पर आधारित स्प्रेड स्पेक्ट्रम को प्रतिष्ठापित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी या निगम या कोई सरकारी संगठन एस ए सी एफ ए द्वारा निर्धारित शर्तों पर "लास्ट माइल कनेक्टिविटी को 2.400 - 2.4835 मेगाहर्ट्स के रेंज में आवृत्ति बैंड को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिष्ठापित करेगी परन्तु यह महत्वम 4 वॉट ई आई आर पी और महत्तम 10 मेगाहार्स के चैनल स्प्रेड को लेकर किया जायेगा । न्यूनतम बाधा को लेते हुए प्रत्येक जिले हेतु 10 मेगाहार्स के दो या तीन चुनीदा सबबैंडों की जिला-वार डायरेक्टरी नियत समयावधि वार बनायी जायेगी । नॉन इंटरफेरेंस, नॉन प्रोटेक्शन, नॉन-एक्स्प्लिबनेस के आधार पर बैंड का प्रयोग होगा, निजी सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और सरकारी प्रचालक डॉट का आवेदन करेंगे और डब्ल्यू पी सी से लाइसेंस एव पंजीकरण लेंगे । सुरक्षा निपटान को अधिगत करने के लिए डॉट एक आंतरिक प्रक्रिया प्रणाली प्रतिष्ठापित करेगा जोकि महत्वम 45 दिवसों में हस्तगत की जायेगी । प्रचालक निगरानी हेतु निर्धारित सुविधाओं को प्रदान करेंगे । डब्ल्यू पी सी निर्धारित शर्तों के उल्लंघन करने में उत्तरदायी होगी और तीन स्तरों यथा लिखित चेतावनी, वित्तीय अर्थ-दण्ड और दो वर्ष निकालने के प्रकारों को लेते हुए दोषियों पर पेनल्टी लगायेगा । रक्षा, डॉट, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, रासूविकेन्द्र और नॉसकाम में से प्रत्येक में से प्रतिनिधि लेकर तकनीकी लेखा-परीक्षा का गठन होगा जिसमें डॉट के सचिव अध्यक्ष होंगे और उपर्युक्त नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे ।
14. यदि ई सी/ई डी आई से संबंधित अपेक्षा को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत सरकारी प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिकी वाणिज्य (ई सी/ई डी आई) के लिए डॉट कम्यूनिकेशन से संबंधित अपेक्षाओं को उनकी प्राथमिकता वर्गीकरण करते हुए उन्हें उच्चतर प्राथमिकता देते हुए उदारवादी रूपरेखा के अंतर्गत दूर-संचार विभाग द्वारा पूरा किया जायेगा ।
15. मल्टीमीडिया की क्षमता रखने वाले सार्वजनिक टेली इंपो केन्द्र (पी टी आई सी),

विशेष-रूप से आई एस डी एन सेवा केन्द्र, रिमोट डॉटा अधिगम, सरकार व समुदाय से संबंधित सूचना प्रणाली, बाजार से संबंधित सूचना, डेस्क टॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीइंफो और इंटरनेट वेब अधिगम सेवा केन्द्रों को सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी और उन्हें बढ़ावा दिया जायेगा । दूर-संचार विभाग और अन्य मूलभूत सेवा संभरक, मूल्य आधारित सेवा संभरक और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्राधिकृत संवर्धनात्मक संगठनों को नान-एक्सक्लूसिव आधार पर इन सेवाओं को बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जायेगी । इन सेवाओं को परिचालित करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा और लागू होने पर सामान्य टैरिफ का डी पी टी आई सी सेवा संभरकों/विशेषाधिकारियों द्वारा भुगतान किया जायेगा । एस टी डी/आई एस डी पी सी ओ को उन्नत करने के लिए दूर-संचार विभाग और अन्य सेवा संभरकों द्वारा इन्हें सुदृढ़ पी टी आई सी में बदलने के प्रयास किये जायेंगे, जिसके लिए इस संबंध में अनिवार्य-रूप से अतिरिक्त निवेश किए बिना प्राथमिकता के आधार पर आई एस डी एन या अन्य डिजीटल सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी ।

16. दूर-संचार विभाग पी सी ओ द्वारा उपलब्ध करायी गयी फेक्स सुविधा तथा मल्टीमीडिया सेवाओं को लाइसेंस न देने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।
17. पी सी और इंटरनेट की गति को देश के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में बढ़ाने के लिए एक ऐसी नीति अपनायी जायेगी जिससे यथायोग्य जोंच के बाद सिविलियन अनुप्रयोगों के लिए उनकी संचार प्रणालियों को रक्षा सेवाओं द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके ।
18. वर्तमान सॉफ्टवेयर केन्द्र वर्ष 2008 तक सूचना-प्रौद्योगिकी के उद्योग के लिए इस समय नियत उच्च लक्ष्यों को स्वयं पूरा करने में सक्षम नहीं होगा । अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव से यह ज्ञात होता है कि हाई-टेक उद्योग आधुनिक टेलीकॉम और संचार-अवसंरचना की सुविधा रखने वाले और उच्च श्रेणी के हाई-टेक शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों में तथा नगरों के समीपवर्ती गांवों के भीतरी प्रदेश में मुख्य-रूप से फल-फूल रहा है । भारत सरकार उपयुक्त नगरों के निकटवर्ती गांवों के भीतरी प्रदेश में ऐसे "हाई-टेक स्थलों" का विस्तार करेगी । इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्वायत्त संरचनाएँ तैयार की जायेंगी और उच्च गुणवत्ता रखने वाले स्वतः स्पष्ट, स्व-वित्त पोषित हाई-टेक स्थल की अवसंरचना को सुगम बनाने के लिए प्रगामी विनियम भी बनाए जायेंगे । प्रारम्भ में बंगलौर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली और भुवनेश्वर नगरों में गांवों के भीतरी प्रदेश में ऐसे पांच हाई टेक स्थल स्थापित करने की योजना बनायी जायेगी और उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा । यह अनुमान है कि कार्य दल द्वारा स्थापित किए जाने वाले सूचना-प्रौद्योगिकी के संबंध में हाई-टेक स्थलों पर

विशेष कार्य दल द्वारा तैयार किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रौद्योगिकी दृष्टि से प्रगामी और प्रशासनिक दृष्टि से उदारवादी अवसंरचना के भीतर उन्हें स्वतंत्र-रूप से एकत्र करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार प्रदान करते हुए कमशः 50 ऐसे हाई टेक स्थलों को व्यवहार्य-रूप से स्थापित किया जा सकता है ।

19. (क) परिभाषा : आई टी सॉफ्टवेयर का अर्थ है कि एक मशीन में पठनीयता के रूप में रिकार्ड किये गये स्रोत कोड और वस्तु कोड को लेकर निर्देशों, डोंटा ध्वनि और इमेज की कोई अभिव्यक्ति जोकि एक प्रयोक्ता को एक स्वचालित डोंटा प्रोसेसिंग मशीन जोकि आई टी उत्पाद शीर्ष के अन्तर्गत आती है उसके माध्यम से प्रभावित करती है या उसे इंटरएक्टिविटी प्रदान करती है । आई टी सेवा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि कोई सेवा जिसके परिणाम वेल्थ एंडिशन को अधिगत करने के लिए आई टी उत्पादों की प्रणाली पर किसी आई टी सॉफ्टवेयर के प्रयोग से परिणाम दर्शाता हो । आई टी उद्योग शब्द आई टी उत्पादों से संबंधित विकास, उत्पादन और सेवाओं को सम्मिलित करेगा । आई टी सॉफ्टवेयर शब्द सभी अधिसूचनाओं में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के स्थान पर बदला जायेगा ।

(ख) वित्त मंत्रालय (सी बी ई सी) कम्प्यूटर, डिजिटल/डोंटा-कम्यूनिकेशन और डिजिटल/डोंटा प्रसारण उत्पादों को शामिल करते हुए "सूचना-प्रौद्योगिकी (आई टी) उत्पाद" नाम का एक नया वर्गीकरण शुरू करेगा जिसमें डब्ल्यू टी ओ (आई टी ए) करार के संलग्नक क (अनुभाग-1 और अनुभाग-11) में दी गयी वर्गीकृत सूची की दिशा में और इन तीन श्रेणियों का प्रगामी प्रौद्योगिकीगत रुपांतरण को समझ रखते हुए और इसके अतिरिक्त डोंटा कम्यूनिकेशन उपकरण से संबंधित जानकारी से अवगत करायेगा ।

(ग) सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर शून्य सीमा शुल्क और शून्य उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी होगा ।

20. सिंगापुर में 13 दिसम्बर, 1996 को मंत्रालय की घोषणा डब्ल्यू टी ओ-आई टी ए मानने वाली भारत सरकार के लिए वित्त मंत्रालय निम्नलिखित नयी सारणी देने हेतु संशोधित अधिसूचना जारी करेगा :

संलग्नक "क" में, डब्ल्यू टी ओ-आई टी ए के अनुच्छेद-1 और 11 में :

क) निम्नलिखित मदों पर 1 जनवरी, 1999 तक ड्यूटी को शून्य तक लाना :

एच एस एन 8473.30 में स्थापित पी सी बी को छोड़कर पुर्जे और संघटक, एच एस एन 8471.70 में सभी भांडारित उपकरण, एच एस एन 8542 में 1000 रुपयों से ऊपर आई सी उपकरण, एच एस एन 8501.10 में स्टेप्पर मोटर्स, एच एस एन 8540.40 में रंगीन ग्राफिक डिस्प्ले ट्यूब और एच एस एन 8504 में कैंलर मॉनिटर के लिए डिफ्लेक्टिव संघटक ।

ख) आई टी ए-1 की 217 मदों की सूची में से 94 मदों की ड्यूटी पहले 1 जनवरी, 2000 तक शून्य पर लाने का प्रस्ताव था जिसे अब 1 जनवरी, 1999 कर दिया गया है ।

ग) बाकी मदों की ड्यूटी को शून्य पर लाने के लिए 1 जनवरी, 2003/ 2004/ 2005 प्रस्तावित था, अब 1 जनवरी, 2002 कर दिया गया है ।

इसके साथ-साथ निम्नलिखित सूची अपनायी जायेगी :

घ) जहां पर भी लागू हो, (ग) में दी गयी मदों के उत्पादन के लिए पूंजी माल पर, ड्यूटी 1 जनवरी, 2001 तक शून्य हो जायेगी ।

जहां पर भी लागू हो (ग) में दी गयी मदों के उत्पादन के लिए इनपुट/कच्चे माल पर 1 जनवरी, 2001 तक शून्य हो जायेगी ।

जहाँ पर भी लागू हो, प्रयोजन की दोहरी मदों पर ड्यूटी हटाने के लाभ देकर या सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग की पूर्तियों को आवश्यक निर्यात समझकर ध्यान में रखा जायेगा ।

शून्य उत्पाद शुल्क के साथ-साथ शून्य सीमा शुल्क में (चरणबद्ध कटौती) सम्पन्न की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त, ऐसे अन्य उपयुक्त समर्थक उपायों को अपनाया जायेगा जिससे संशोधित डब्ल्यू टी ओ-आई टी ए कार्य-विवरणिका को ध्यान में रखते हुए भारतीय हार्डवेयर उद्योग को विश्व-व्यापी बाजार में प्रतियोगी के रूप में स्थापित किया जा सके ।

21. सी डी-रॉम या ऑप्टिकल डिस्क मीडिया या मैग्नेटिक मीडिया जिसमें टेक्स्ट, डेटा अथवा मल्टीमीडिया के विषय-विवरण समाहित हो, उनमें केवल मीडिया-सामान के आयात पर सीमा शुल्क लगाया जायेगा न कि विषय-विवरण की वस्तुओं पर ।
22. आयातित सूचना-प्रौद्योगिकी के उत्पादों को बंधित कार्यालयों या ई ओ यू/ई पी जेड/एस टी पी/ई एच टी पी योजनाओं के अंतर्गत आयात की तिथि से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक्स/आई टी यूनिटों से बाहर ले जाने की अनुमति दी जायेगी परन्तु ये वस्तुएँ एक सीमा शुल्क की अधिसूचना के जरिये ऐकिसम पॉलिसी की प्रक्रिया हैडबुक के अनुच्छेद 2.19 में दर्शाये गये अनुसार मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, सरकारी संगठनों और रजिस्टर किये गये धर्मार्थ चिकित्सालयों को दानरूप में दी गयी हों ।
23. सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना-प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियों जो कि जानकारी के उद्योग के अवयव के रूप में हैं, फैक्टरी, बॉयलर, उत्पाद-शुल्क, श्रमिक संस्थान, प्रदूषण/पर्यावरण आदि के लिए नियुक्त निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण की छूट दी जायेगी ।
24. वाइड एरिया कम्यूनिकेशन नेटवर्क में प्रौद्योगिकीगत संवर्धन कार्यक्रमों को लेकर जो कि "वर्चुअल टेक्नोलॉजी पार्कों" के रूप में समझ आये हैं जिनमें देश में अलग-अलग स्थलों से सॉफ्टवेयर और सेवा उप-प्रणालियों के प्रत्यक्ष समन्वयन द्वारा सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाएँ विकसित की जा रही हैं वहाँ फिजिकल बॉडिंग की संकल्पना अब अप्रचलित हो गयी है । तदनुसार एस टी पी/ई ओ यू/ई पी जेड आदि को शामिल करते हुए अन्य निर्यात संवर्धन योजनाओं में सॉफ्टवेयर विकासकर्त्ताओं/निर्यातकों को सीमा-शुल्क की बॉडिंग से छूट दी जाती है । ई पी सी जी योजना के तहत दिये गये उन्हीं मूल्यों पर निर्यात बाध्यताएँ लगायी जायेगी । उपर्युक्त योजना के तहत विभिन्न सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान बंधित यूनिटों पर भी विचार किया जायेगा ।
25. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकास उद्योग पर सर्विस कर लागू न होने के संदर्भ में सी वी ई सी द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया जायेगा ।
26. नागर विमानन मंत्रालय विनिमयों में निम्नलिखित अधिसूचना/संशोधन जारी करेगा :

वायु कार्यों के लिए निर्यात नौभार समय को 24 घण्टों की समयावधि से कम कर दिया जायेगा ।

शीतलन अवधि के कारण हुए विलम्ब को दूर करने के लिए "नोन शिपर" को शुरू किया जायेगा ।

कार्गो कम्पनियों और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्यात संबंधी वायु कार्गो को समेकित करने की अनुमति दी जायेगी ।

27. आयकर अधिनियम की धारा 80 एच एच ई में सॉफ्टवेयर और सेवा निर्यात से हुए लाभ पर आयकर छूट प्रदान की गयी है । इस खण्ड में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे :

वर्तमान फार्मुला ऐसे बदला जायेगा कि घरेलू बिक्री के लाभ पर कर से कोई संबंध नहीं होगा ।

सूचना-प्रौद्योगिकी के सेवा निर्यातों को शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर और निर्यात बिक्री की परिभाषा को बदला जायेगा ।

निर्यातों से हुए लाभ पर आयकर छूट के लिए इस खण्ड में दिये लाभों को सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना-प्रौद्योगिकी सेवा विकास कर्त्ताओं के समर्थन में बढ़ाया जायेगा ।

28. आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 10(15) (iv) के सीमित उद्देश्य के लिए लागू होने पर सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाओं को विनिर्माण कार्यकलापों की तरह समझा जायेगा ।

29. सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाओं को आयकर अधिनियम की धारा 9 के स्पर्डीकरण में संशोधन करके पहिले ही लगे करों से मुक्त किया जायेगा

30. देनदार से कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लिया जायेगा या 50 हजार रुपये के वास्तविक खरीद मूल्य के पी सी के लिए लेनदार पर भी आयकर नहीं लगेगा ।

31. सूचना-प्रौद्योगिकी उत्पादों और सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर पर किये गये निवेश पर दो साल में 100% मूल्यहास की छूट दी जायेगी, जिसके लिए वित्त मंत्रालय उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।

32. जैसा कि कार्यकारी कुंजी की संपत्ति आधारित वित्तपोषण के पुराने तरीके से सॉफ्टवेयर क्षेत्र में वित्त पोषण की आवश्यकताओं को समय से और पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा सकता, अतः उद्योग की अपनी अलग प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में कार्यवाही कुंजी की अपेक्षाओं में विशेष छूट देकर एक विशिष्ट और प्रत्यास्थ दृष्टिकोण अपनाया जायेगा । तदनुसार, 15 अगस्त, 1998 को भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य मापदण्ड जैसे कुल बिक्री पर आधारित सेवा क्षेत्र और सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के लिए कार्यवाही कुंजी आवश्यकताओं के संबंध में नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करेगा । बैंकों को सलाह दी जायेगी कि अनुबन्ध मूल्यों का 25% 18 महीनों के लिए प्रदान किया जाये, जिसमें पहले 6 महीनों में अवधि कर्ज (बिना कॉलेटरसर्स के) और 7 महीने के बाद कॉलेटरलों के स्थान पर वार्षिक केश फ्लो स्टेटमेंट्स स्वीकार किये जायेंगे ।
33. अगले पांच वर्षों के लिए बैंकों द्वारा सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर एवं सेवा उद्योगों को एक प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जायेगा । इसे सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात और देश में सूचना-प्रौद्योगिकी और उनकी उपयोग की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद मिलेगी । मुख्य बैंकों को परामर्श दिया जायेगा कि वे अपनी मुख्य शाखाओं में विशिष्ट सूचना-प्रौद्योगिकी वित्तीय प्रकोष्ठों को खोलने में जहाँ सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सेवा यूनिटें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों । वित्त मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में किये कार्य की निगरानी की जायेगी ।
34. इस उद्योग के लिए वर्तमान अनुमानित 400 करोड़ रुपये की कुंजी को बढ़ाकर सन् 2000 तक लगभग 1200 करोड़ किया जायेगा जो वर्तमान में वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि की तुलना में अगले 24 महीनों की बढ़ती हुई प्रत्याशित आवश्यकताओं की बृहद प्रक्रिया के यथानुपात के आधार पर होगी, इसलिए एक प्रणाली शुरू की जायेगी जो बैंकों द्वारा प्रदान की गयी कार्यशील पूंजी में अत्यधिक वृद्धि करेगी ।
35. बैंकों द्वारा ऋण दिये गये सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यातकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम ब्याज दरों पर दुबारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पात्र बनाया जायेगा ।
36. सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग में 5% की वृद्धि की चालू जमा राशि के शेयरों की अनुमति के संबंध में समर्पित उद्यम जमा पूंजी में समतुल्यता के रूप में निवेश हेतु बैंकों को अनुमति प्रदान की जायेगी ।

37. उद्योग की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजीगत समर्पित निधि से कम से कम 4 विभिन्न उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक/वित्तीय संस्थाएँ जैसे आई सी आई सी आई, आई डी वी आई, यू टी आई और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भारतीय या विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करेगा ।
38. ऐसे उद्यम के पूंजीपतियों को आयकर के लिए ब्लॉक वर्षों के दौरान किसी एक कम्पनी में निवेश पर घाटा भी हो सकता है और किसी अन्य कम्पनी में निवेश पर लाभ ।
39. 1997 के कम्पनी बिल के खण्ड 73 व 74 (7) (6) में स्वीट-इक्विटी के लिए एक नया परन्तुक जोड़ा जाएगा : "कम्पनी में वेल्यू एडीशन या जानकारी, बौद्धिक सम्पत्ति प्रदान करने के लिए कर्मचारियों या पूर्णकालिक निदेशकों या उनके प्रमोटर डायरेक्टरों को भी स्वीट-इक्विटी भारत में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनियाँ या विदेशों में उनकी सबसीडरियों द्वारा जारी की जाएगी जो कि सेबी या केन्द्र सरकार जैसा भी मामला हो द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर अमल में लाई जाएगी ।" खण्ड 2 में पारिभाषा संख्या 65 के बाद एक नयी परिभाषा संख्या 66 इस प्रकार से जोड़ी जाएगी ।

"स्वीट-इक्विटी से अभिप्रायः है कि प्रमोटर डायरेक्टरों, पूर्णकालिक निदेशकों या कर्मचारियों को कोई जानकारी, बौद्धिक सम्पत्ति या कम्पनी को वेल्यू एडीशन प्रदान करना ।

40. कम्पनियों की दोहरी सूचीकरण के लिए तथा ए डी आर/जी डी आर के लिए द्वितीय प्रतिमोचिता पर विचार करते हुए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों को जारी करते समय वित्त मंत्रालय सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना-प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र को शामिल करेगा ।
41. भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए डालर से संबद्ध स्टॉक विकल्पों की घोषणा 1998 के बजट में गई थी और इस संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त डी ई ए. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये । इसमें ऊपर (19) (क) और (ख) में दिए गए अनुसार सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाओं की परिभाषा के अनुसार संशोधन किया जायेगा ।

भारत में स्टॉक सूची के लिए कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जायेगा । इसके साथ ही, यह स्पष्टीकरण भी जारी किया जायेगा कि आयकर केवल बिक्री के समय ही लागू होगा न कि वह विकल्प देने के समय लागू होगा ।

42. व्यापार की अत्याधिक तेजी को समझ रखते हुए आई टी सॉफ्टवेयर और आई टी सर्विस निर्यातकों द्वारा प्रभावित होने वाली अत्याधिक प्रतियोगिता और तीव्रगति से होने वाली प्रौद्योगिकीगत अप्रचलनता के कारण भारतीय रिजर्व बैंक, एक इंटर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप (आई आई जी ) प्रतिष्ठापित करेगा जो कि एक महीने के भीतर निम्नलिखित संस्थानों को अधिकतम रूप से समायोजित करेगा :

- क) सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए बोर्ड से परे सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए/सॉफ्टवेयर अर्जन करने हेतु विदेशी निवेश के लिए तथा यू एस डालर 25 मिलियन से अधिक पिछले 3 वर्षों में की गयी संचयी वास्तविक निर्यात वसूली के लिए खुला अनुमोदन पिछले तीन वर्षों में उपार्जित संचयी वास्तविक निर्यात राशि में से 50% राशि या यू एस डालर 25 मिलियन, जो भी कम है, के लिए दिया जायेगा । यह अनुमोदन उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा ।
- ख) इस सीमा से परे फेरा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक इस क्षेत्र से प्राप्त अनुपयोगों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए एक प्रक्रिया प्रणाली स्थापित करेगा । इसकी 15 अगस्त, 1998 को घोषणा की जायेगी ।
- ग) समुद्री उद्यमों हेतु सामान और सेवाओं दोनों को पूंजी प्रदान करने के लिए छूट दी जायेगी, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श करते हुए इसे तदनुसार 15 अगस्त, 1998 तक अधिसूचित करेगा ।
- घ) चूंकि विदेशों में व्यय करने के लिए संचिता राशि की मौजूदा स्वीकृत सीमा 70% राशि निर्धारित की गई है, इसलिए उसमें कार्य व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से या सामान्य निगमित लक्ष्यों के उद्देश्यों से इनका प्रयोग प्रत्यास्थता प्रदान नहीं करता, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक सूचना-प्रौद्योगिकी निर्यातकों को पूरी प्रत्यास्थता प्रदान करने के लिए विभिन्न/ फुटकर उद्देश्यों के लिए विदेश में निर्यात की (कुल 70% कुल प्राप्तियों की राशि में से) 5 % राशि स्वतंत्र रूप से खर्च करने की अनुमति प्रदान करेगा । 70% राशि में से स्वीकार्य व्ययों की एक नयी सूची कार्यान्वित की जायेगी ।
- ड) दूसरे स्तर की और उच्च स्तरीय आर्थिक सहायता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिगत न होने वाली राशि में अवरोधों को समाप्त करने के लिए ई ई एफ सी की मार्गदर्शी

विवरणिका जारी करेगा, और निम्नलिखित पर ई ई एफ सी के शेष राशियों के 20% उपयोग के लिए अनुमति देगा :

- i) सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग के लिए अग्रिम रकम भेजना (प्रति 1 लाख अमेरिकी डालर तक के कार्य-व्यापार करने पर)
  - ii) उपकरण की खरीद और उससे संबंधित व्यय ।
  - iii) विविध खर्च जिनका ई ई एफ सी के मार्गदर्शी सिद्धांतों में विस्तार से (5% तक) विवरण नहीं दिया गया है इस प्रकार के ई ई एफ सी खातों को सीधे ही भारतीय बैंकों की समुद्र तटीय शाखाओं से भुगतान करने की अनुमति दी जायेगी ।
- घ) सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्रों द्वारा अपेक्षित विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (आई सी सी) का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कराया जायेगा और इसको 15 अगस्त, 1998 तक विशेष रूप से अधिसूचित किया जायेगा ।
- i) विनिमय विदेशी मुद्रा उपार्जन (ई ई एफ सी) खाता के अंतर्गत दिये गये सभी प्रकार के चालू भुगतानों को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (आई सी सी) के माध्यम से करने की अनुमति भी दी जायेगी । सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के अग्रिम भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने की अनुमति दी जायेगी जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक अधिसूचना जारी करेगा । इस आशय की अधिसूचना जारी की जायेगी कि इंटरनेट या एफ्टरनेट पर सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सूचनाएँ प्रदान करने के लिए और क्षेत्र के नामों का पंजीकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग भी किया जायेगा ।
  - ii) भारतीय रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का निर्यात करने हेतु अपेक्षित परिशोधित और सरलीकृत सॉफ्टवेक्स फार्म 15 अगस्त, 1998 तक जारी करेगा ।
43. ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत एक स्व-व्योषणा प्रणाली शुरू की जायेगी जिसमें 100% पोस्ट बैंकिंग को अपनाया जायेगा, परन्तु गलती होने पर अधिक दण्ड लगाया जायेगा ।

44. निजी कंप्यूटरों तथा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के आयात के लिए मूल्य सीमा को 1.50 लाख रुपये (सी आई एफ) से घटाकर 70 हजार रुपये (सी आई एफ) कर दिया जायेगा ।
45. सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदान करने वाली निजी और सार्वजनिक संगठनों के पूंजीगत माल का आयात करने हेतु शुल्क में छूट दी जायेगी । ऐसे आयातित पूंजीगत माल को मध्यमजर रखते हुए ऐसे सेवा संभरक ई पी सी जी योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल का आयात करने के लिए दी गयी निर्यात वाध्यताओं के अनुसार कार्य शुरू करेंगे ।
46. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रचालित भारत की ब्रांड इक्विटी निधि योजना को कम समयावधि और कम ब्याज पर सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए उपलब्ध कराया जायेगा ।
47. स्थल पर सूचना-प्रौद्योगिकी की सेवाओं को विदेशों में भारतीय मिशन और विदेश मंत्रालय द्वारा नियोजित व्यवहारिक नीति के माध्यम से प्राप्तकर्ता देशों के वीजा-विनियमों के अनुसार सुगम बनाया जायेगा और उनके लिए विदेश मंत्रालय एक उपयुक्त समर्पित संरचना विनिर्मित करेगा । इसमें समग्र समझौता दस्तावेजों पर आवश्यकता पडने पर हस्ताक्षर करना भी शामिल होगा जिससे कि जहाँ कहीं अनिवार्य हो भारतीय कंपनियों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को कायम रखा जा सके ।
48. पैकेज सॉफ्टवेयर के विकास कार्य में वृद्धि की जायेगी जिससे विदेशों में शोक कंपनियों को स्थापित करने के लिए भारतीय विपणन कंपनियों को सक्षम बनाया जा सके । उन्हें इंटरनेट के माध्यम से भारत से पैकेज सॉफ्टवेयर का विपणन करते हुए और अधिक प्रत्यास्थ बनाया जायेगा ।
49. अपने देश को उभरते हुए अपने प्रतियोगियों के समक्ष बेचमाकिंग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिष्ठित परामर्शदायी कंपनियों द्वारा सरकारी लागत पर दो वर्षों में एक बार इस संबंध में अध्ययन किया जायेगा ।
50. आवासीय क्षेत्रों में सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाएँ और सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर (जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण भी शामिल है) से संबंधित कंपनियों की अवस्थिति पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों को हटाया जायेगा ।
51. संगठन और कंपनियों को राष्ट्रीय और निगमित रूप से वाई-2 के और यूरो जैसे

"लार्जनिचे मार्केट्स" के लिए योजना नीतियों की पहचान करने और उनकी खोज करने के कार्य में सक्षम बनाने के उद्देश्य से सभी योग्य प्रावधानों को उच्च प्राथमिकता आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा । एम ओ सी और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की वित्त राशि के माध्यम से "भारतीय पेवेलियन" को ई एस सी और एन ए एस एस सी ओ एम के समन्वय से और उस कार्य में पड़ल करतें हुए विश्वभर में सूचना-प्रौद्योगिकी के संबंध में बहुत-सी मुख्य प्रदर्शनियों के अन्तर्गत प्रतिष्ठापित किया जायेगा ।

52. विश्वभर में वाई-2 की समस्याओं को सुलझाने के लिए 1000 बिलियन डालर खर्च किये जा रहे हैं । इसके महत्व को पहचानते हुए महत्वपूर्ण सरकारी, सार्वजनिक और निजी संगठनों और सेवा संगठनों में पैदा होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए कॉरपस निधि के रूप में 700 करोड़ रुपये का तुरन्त निवेश किया जायेगा । इस विपदा का सामना करते हुए देश में ऐसे संगठनों को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये जायेंगे और उसका समबद्ध तरीके से कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सरकारी आदेश जारी किये जायेंगे । उच्च स्तर के शक्ति सम्पन्न कार्यदल को भारत सरकार द्वारा गठित किया जायेगा जिसमें सरकारी संगठनों, उद्योग संघों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, रक्षा सेवाओं, उपयोगिता और अन्य सार्वजनिक सेवा संगठनों और अन्यो में रेलवे के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे ।
53. "भैगा वेब साइट" की अधिक प्रयासों के जरिए भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों और पैकेजों को प्रोत्साहित करने और विपणन को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट पर विनिर्मित किया जायेगा ।

भारत में स्थित सर्वरों पर वेब साइट को विनिर्मित करने और उसे स्थापित करने के कार्य को बढ़ावा दिया जायेगा ।

54. इलेक्ट्रॉनिकी और सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् (ई एस सी), एस टी पी आदि द्वारा संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करते हुए डी ई पी बी के व्यापार संबन्धी करार के अधीन रुस में सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर, सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाएँ और सूचना-प्रौद्योगिकी के उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी ।
55. सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना-प्रौद्योगिकी सेवा के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सभी संवर्धनात्मक और उदार नीति के प्रपत्रों को सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और

सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाओं के समक्ष सूचना-प्रौद्योगिकी में सक्षम सेवाओं का वर्गीकरण करते हुए सूचना-प्रौद्योगिकी में सक्षम सेवाएँ तथा सूचना से संबंधित उद्योगों तक उपलब्ध कराया जायेगा ।

56. भारतीय सॉफ्टवेयर पैकेज (प्रणाली तथा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर) को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पैकेज खरीद कर प्रयोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा । भारत में विकसित बहुत ज्यादा उपयोगी पैकेजों की पहचान करने के लिए विशेष जॉइंट प्रणाली कार्यान्वित की जायेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी स्वीकृति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार तथा उद्योग द्वारा पर्याप्त सहायता प्रदान की जायेगी ।
57. अन्य कार्यकलापों में (4),(7),(8), (12),(13),(24),(43), (45),(54) और (55) के अधीन दिये गये प्रावधानों को शामिल करने के लिए निजी एस टी पी को स्थापित करने के कार्य को प्रोत्साहित किया जायेगा ।
58. सरकार शीघ्र ही "विद्यार्थी कम्प्यूटर योजना", "शिक्षक कम्प्यूटर योजना" और "विद्यालय कम्प्यूटर योजना" नामक तीन योजनाएँ शुरू करेगी जिससे कि कम्प्यूटर खरीदने के इच्छुक विद्यार्थी, शिक्षक या स्कूल आकर्षक वित्तीय पैकेज के अधीन कम्प्यूटर खरीद सके । पी सी को कम लागत पर उपलब्ध कराने, आसान किस्तों पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराने, सूचना-प्रौद्योगिकी से संबंधित कम्पनियों और अन्य व्यापार गृहों द्वारा कम्प्यूटर दान आधार पर प्रदान करने, एन आर आई संगठनों द्वारा कम्प्यूटर के संबंध में काफी ज्यादा दान कर के आयात के संबंध में बड़ी मात्रा में मूल्यों में कमी करके, बहु-आयामी वित्त-पोषण आदि प्रदान करने जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू करते हुए इन योजनाओं को संवर्धित किया जायेगा ।
59. वर्ष 2003 तक देश में प्रत्येक स्कूल, पॉलिटेक्निक, कालेज, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में कम्प्यूटर और इंटरनेट सेवाएँ जोड़ी जायेगी ।
60. देश में उच्च शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों, सभी विश्वविद्यालयों, इंजीनियरी कालेज, चिकित्सा कालेज और अनुसंधान और विकास संगठनों को वर्ष 2000 से पहले शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से दूरस्थ शिक्षा के अनुपूरक कार्यक्रमों के लिए नेटवर्क से जोड़ा जायेगा ।
61. इन कार्यक्रमों को उपयुक्त रूप से पुनः सृजित करते हुए सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या संबंधी क्षमता को तीन गुना करने के उद्देश्य से 7 राष्ट्रीय स्तर के

- संस्थानों (आई आई टी, भा.वि.प्रौ.) को बढ़ावा दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित सॉफ्ट केप परियोजना 300 करोड़ रुपये की नवीं पंचवर्षीय योजना की बचनबद्धता को लेकर कार्यान्वित की जाएगी ।
62. सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से होने वाले विकास को मदद-नजर रखते हुए अलग-अलग पाठ्यक्रमों और उनकी विषय-सूची के लिए उद्योग और शैक्षणिक संस्थान दोनों से विशेषज्ञों को लेते हुए राष्ट्रीय सूचना-प्रौद्योगिकी की शिक्षा परिषद् को ए आई सी टी ई के एक हिस्से के रूप में गठित किया जायेगा । यह परिषद् अध्यापकों की सूचना-प्रौद्योगिकी में जानकारी और दक्षता को नियमित आधार पर बढ़ाने के लिए "टीच द टीचर" (3 टी) कार्यक्रम भी शुरू करेगी ।
63. सूचना-प्रौद्योगिकी की पाठ्यक्रम के मॉड्यूल को थोड़े ही समय के भीतर सभी डिग्री पाठ्यक्रमों का अनिवार्य सगठन-अवयव बनाया जायेगा ।
64. गैवाये गये समय की पूर्ति की अत्यावश्यकता को देखते हुए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी) के गठित करने के कार्य को कार्यान्वित किया जायेगा । भारतीय सूचना-प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) जैसे हाई-टेक संस्थानों को कानूनी रूप से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जायेगा ।
65. सूचना-प्रौद्योगिकी के संबन्ध में सरकार हमारे विश्वविद्यालयों को विकसित देशों के उत्कृष्ट केन्द्रों से जोड़ने के कार्य को बढ़ावा देगी ।
66. सॉफ्टवेयर विपणन पर विशेष पाठ्यक्रम विकसित करने और परियोजना प्रबन्धन दक्षता उपलब्ध कराने के लिए सॉफ्टवेयर उद्योग और आई आई एम के सहयोग से विशेष पाठ्यक्रम शुरू किये जाएंगे ।
67. "स्मार्ट" स्कूल की संकल्पना को प्रत्येक राज्य में प्रायोगिक प्रदर्शनात्मक आधार पर शुरू किया जायेगा जिसमें स्कूलों में सूचना-प्रौद्योगिकी पर भी बल ही दिया जाएगा अपितु कई वर्षों में आगे आने वाले महत्वपूर्ण मूल्य और दक्षता का इस्तेमाल करने पर बल दिया जाएगा ।

68. भारत के कम्प्यूटर व्यावसायियों के लिए संस्था को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इण्डिया के पैटर्न पर स्थापित किया जाएगा । इस संस्था को उद्योग और सरकार से प्रारम्भिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए एन ए एस एल सी ओ एम द्वारा केन्द्रीकृत बनाया जाएगा । इस संस्था को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के डी ओ ई ए सी सी के कार्यक्रम के अतिरिक्त सरकार की पूरी मान्यता प्रदान करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रत्यायन निकाय के रूप में जिम्मेदारी प्रदान की जाएगी ।
69. सभी स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा पर आधारित जानकारी में वृद्धि करने के लिए सरकार ने सशस्त्र सेना की मौजूदा जनशक्ति में से सूचना प्रौद्योगिकी, प्रणाली इंजीनियरी और सूचना-प्रौद्योगिकी के सुरक्षा संस्थान स्थापित करेगी । राष्ट्रीय लाभार्जन के लिए रक्षा सेवाओं के प्रणाली इंजीनियरी और सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टर्स ऑफ एक्सलेंस) का इस्तेमाल किया जाएगा ।
70. दूरस्थ शिक्षा में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न भागों में वर्चुअल इंस्टीट्यूट्स स्थापित किये जाएंगे ।
71. शीघ्र ही भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित भूतपूर्व कर्मचारियों की दक्षता और सुविज्ञता का इस्तेमाल किया जाएगा और सरकार सशस्त्र बलों के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से समर्थन प्रदान करेगी । उप जिला स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी की संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रत्येक वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी में साक्षर काफी संख्या में सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए योजना तैयार की जाएगी और उसे कार्यान्वित भी किया जायेगा ।
72. जानकारी अर्जन करने के संबंध में कम्प्यूटरीकृत प्रत्यक्ष वस्तुनिष्ठ प्रणाली के लिए "राष्ट्रीय योग्यता संबंधी ढांचा" स्थापित किया जाएगा । डिप्लोमा और डिग्री हेतु पात्रता के संबंध में विभिन्न संस्थानों/प्रणालियों में उपार्जित समन्वित क्रेडिट कार्यक्रमों को प्रत्यास्थता प्रदान करने के लिए "शैक्षणिक क्रेडिट बैंक" कार्यान्वित किया जायेगा ।
73. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डिजिटल पुस्तकालयों संबंधी परियोजनाओं के लिए एक विशेषज्ञ समिति के कार्यक्रमों के संयोजन और उसके प्रतिष्ठापन के लिए बनाई जाएगी ।

74. इन जिलों में सभी माध्यमिक स्कूलों में विश्वस्तरीय कम्प्यूटर साक्षरता प्राप्त कराने के उद्देश्य से विश्वस्तरीय साक्षरता प्राप्त कुछ प्रमुख जिलों में सूचना एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जाएगी । इसके साथ-साथ उच्च स्तर की शिक्षा अवसंरचना पर विश्व श्रेणी की दक्षता पैदा करने के उद्देश्य से इन जिलों में शैक्षणिक संस्थानों के नेटवर्क के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रादुर्भाव कराने के कार्य में सहायता प्रदान की जाएगी । यह प्रायोगिक परियोजनाएं स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों, संबद्ध राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के लिए संयुक्त प्रयासों से कार्यान्वित की जाएगी ।

प्रथम चरण में ऐसी प्रायोगिक परियोजनाओं को सतत स्व-वित्तपोषित आधार पर कर्नाटक में उडुपी जिलों और दक्षिण कन्नड में शुरू किया जाएगा । कुछ ही समयावधि में अन्य राज्यों में योग्य जिलों तक इस सुविधा को बढ़ाया जाएगा ।

75. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर-पूर्वी राज्यों में राष्ट्र के औसत स्तर से निचले स्तर पर तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा सुविधाओं के मददेनजर सभी स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उन्हें मॉडल प्रदान करने दृष्टि से अनेकों शैक्षणिक केन्द्रों को पहिचाना जाएगा । इस पहल का यह उद्देश्य होगा कि ज्ञान और ज्ञान आधारित उद्यमों के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और उसमें जागरूकता को बढ़ावा मिले ऐसे प्रथम मॉडल के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा व व्यापार केन्द्र को इलाहाबाद में विकसित किया जाएगा । थोड़े ही समय में इस प्रारम्भिक कार्य को सूचना प्रौद्योगिकी में विकासशील अन्य राज्यों तक बढ़ाया जाएगा ।
76. सरकार जनता को "एक स्थल पर अविरल रूप से" सेवाएं प्रदान करने के लिए ए टी एम, इलेक्ट्रॉनिक्स कियोस्क, टेलीफोन, स्मार्ट-कार्ड आदि को लेकर मूल्य आधारित नेटवर्क सेवाओं का गठन करने के कार्यों को प्रोत्साहित करेगी ।
77. सूचना प्रौद्योगिकी को बहुत ज्यादा गतिशील बनाने के लिए जागरूकता पैदा करने वाली नीति दो माह के भीतर कार्यान्वित की जाएगी और उसे कार्यान्वित करने के लिए संरचना को प्रस्तुत किया जाएगा ।
78. भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए बृहत् सवर्धनात्मक अभियान शुरू किया जाएगा । यह अभियान बहु-आयामी दृष्टिकोण को लेकर चलाया जाएगा और उसमें भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का प्रचार और विपणन, उत्पादन, अनुसंधान

और विकास के लिए राजकोषीय और अन्य प्रोत्साहन शामिल होंगे । यह सिफारिश इस तथ्य को दर्शाती है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ी शक्ति तभी प्राप्त करेगा जब वह देश में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव को और गहरा करेगा और उसमें प्रसार-प्रचार करेगा जो इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो ।

79. सरकार कृषि और समन्वित ग्रामीण विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी । इस दिशा में, स्थानीय स्तर पर विशिष्ट शक्ति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य में बहुत सी प्रदर्शन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी । महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में वारणानगर सहकारी कॉम्प्लेक्स में सूचना प्रौद्योगिकी पर एकमात्र "वायर्ड विलेजिज" प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है । अन्य राज्यों में ऐसी परियोजनाओं को शीघ्रता से करने के प्रयास किये जाएंगे ।

80. सरकार ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी का काम लागत पर विस्तार करने, राष्ट्रीय उद्देश्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए बायरलैस टेलीकम्यूनिकेशन के कार्यकलापों के अंतर्गत स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और घरेलू और सार्वभौमिक बाजार में उनको विकसित करने, निर्मित करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी । इसी प्रकार केवल टी.वी. हाउसों के बृहत् नेटवर्क के माध्यम से जनता तक इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी को पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सर्वधनात्मक उपाय किये जाएंगे ।

81. समयबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन बोर्ड की दसवीं बैठक में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार बंदरगाहों, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, डी.जी.एफ.टी. बैंक, कन्टेनर सेवाएं, सीमा शुल्क और भारतीय रेलवे को कड़े निर्देश दिये जाएंगे ।

82. देश में बेची गई प्रत्येक मद की बार-कोडिंग 5 वर्ष की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से की जाएगी ।

83. सशस्त्र बल अपनी नागरिक, कार्रवाई से संबंधित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव के माध्यम से भारत की मुख्य धारा से सुदूर और दूरस्थ क्षेत्रों (लद्दाख, उत्तरी-पूर्वी राज्य, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, कच्छ लक्षद्वीप और

मिनीकॉप औपसमूह, हिमाचल और राजस्थान के सीमा क्षेत्र) को जोड़ेगे । इस प्रारम्भिक कार्य के लिए वित्त राशि सरकार/उद्यम/सीड-केपिटल के माध्यम से मुहैया करायी जाएगी ।

#### 84. नागरिक सूचना प्रौद्योगिकी इंटरफेस

मंत्रिमंडल ने सुरक्षा रखने के अलावा जनता को सरकारी सूचना उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है । इस निर्णय को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र को ऐसा करने के लिए उपयुक्त शक्तियाँ प्रदान करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा । सरकारी सूचना की गहन पारदर्शिता और उसे आसानी से उपलब्ध कराने की आवश्यकता को महसूस करते हुए यह सिफारिश की गई है ।

85. जिला सूचना प्रणाली (डिसनिक) योजना कार्यक्रम को व्यापक बनाया जाएगा और सीधे ही अद्यतन किये गए डेटाबेसों की अन्यो के साथ-साथ जनता और पेचायत तक उपलब्ध कराया जाएगा । न्यायालय सूचना प्रणाली (कोर्टिज) संसद सूचना प्रणाली (पारलिस) कंप्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली कार्यक्रम (किप्स) और अन्य डेटाबेसों को निकनेट पर सीधे ही अद्यतन किया जाएगा और उसे जनता तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जाएगी ।

86. जनता तक समयबद्ध सेवाओं के सबध में प्रभावी और सक्रिय प्रशासन व्यवस्था के लिए एक नागरिक अधिकार-पत्र को प्रशासनिक सुधार और जन-शिकायत विभाग के समन्वयन से प्रस्तुत व कार्यान्वित किया जाएगा और उसे भारत सरकार के शासकीय इंटरनेट वेब साइट "इंडिया इमेज" पर प्रदर्शित किया जाएगा । डी ओ पी व टी सिटिजन आई टी इंटरफेस से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करेगा ।

#### सरकार में सूचना-प्रौद्योगिकी

87. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में प्रत्येक विभाग/एजेन्सी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना-प्रौद्योगिकी की गतिविधियों पर पंचवर्षीय योजना तैयार करे ।

88. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के बजट के 1.3 प्रतिशत भाग को विभाग/क्षेत्र में सूचना-प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करने के लिए नियत किया जाएगा और इस निवेश में न केवल सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की खरीद शामिल होगी अपितु इसमें सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और प्रशिक्षण भी शामिल होगा । सूचना-प्रौद्योगिकी के उप-बजट शीर्ष के लिए पुनर्विनियोजन विभागाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ही किया जाएगा ।

89. राज्य स्तर पर प्रौद्योगिकी सेवा संगठन और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र प्रलिखित सफलावरों के साथ "फ्रेमवर्क संविदा" स्थापित करेगा जिससे कि थोक खरीद के माध्यम से कम लागत पर लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों को सूचना-प्रौद्योगिकी उत्पादों और सूचना-प्रौद्योगिकी परामर्शदायी, सेवाओं विशेषज्ञ सेवाओं की व्यापक श्रेणी प्रदान की जा सके ।
90. भारत जी-8 देशों की "सरकारी प्रत्यक्ष" परियोजना जैसी अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भाग लेगा जिससे कि सरकार में सूचना-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अन्य इयक्तियों के अनुभव से कुछ सीखा ही न जाए अपितु उनमें विश्वस्तरीय अनुभव का योगदान भी दिया जा सके ।
91. टेलीकंप्यूटिंग की कार्यालय में कार्य करने की नई पद्धति के रूप में पहचान की गई है और उसको समयोजित करते हुए मजदूर कानून बनाये जाएंगे । "उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन" (एम.बी.ओ.) की संरचना के अन्तर्गत टेलीकंप्यूटिंग के माध्यम से उनके कार्य के भाग को पूरा करने के लिए व्यवहार्य और कार्य दक्ष होने पर कर्मचारियों को विकल्प दिया जाएगा ।
92. भारत सरकार राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के साथ सरकार के डोंटा संबंधी उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय आगार स्थापित करेगी और उसे निकनेट के माध्यम से अधिगम योग्य बनाएगी ।
93. मंत्रिमंडल सचिव के अधीन सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित मानचित्र और भौगोलिक सूचना-प्रणाली से संबंधित डोंटा-नीति के लिए टी जी/मेप समिति की सिफारिशों को रक्षा मंत्रालय द्वारा शीघ्रता से अधिसूचित किया जाएगा ।
94. विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण की कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय वस्तु सूची तैयार की जाएगी ।
95. इलेक्ट्रॉनिकी अधिगम हेतु सरकार की उत्कृष्ट पद्धतियों के संबंध में एक कम्प्यूटरीकृत वस्तु सूची बनाई जाएगी ।
96. सरकार सभी भावी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र केरोजगार के लिए अनिवार्य अपेक्षा के रूप में सूचना-प्रौद्योगिकी साक्षरता को निर्धारित करेगी और विभाग/संगठन में सूचना-प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए दिये जाने वाले योगदान के संबंध में सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में एक कॉलम शुरू किया जाएगा ।

97. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्मेंट को सूचना प्रौद्योगिकी में सहायता प्रदान करने वाले व्यवस्था-तंत्र से संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए गठित किया जाएगा।
98. सूचना-प्रौद्योगिकी के संबंध में राज्य सरकारों को मदद प्रदान करने के लिए राज्य जन-प्रशासन संस्थान को पुनः विनिर्मित किया जाएगा ।
99. सूचना-प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए सरकारी कर्मचारियों का अनुपातिक संख्या में निशुल्क नामांकन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से निजी शैक्षणिक संस्थानों को कार्यालय समय के बाद इस्तेमाल न किये जाने वाले सरकारी भवनों में उपयुक्त स्थल दिया जायेगा ।

### डॉटा सुरक्षा प्रणाली और साइबर कानून

100. एस ए जी, जे सी बी , डब्ल्यू ई एस ई ई आदि द्वारा तैयार किये गये इसी प्रकार के दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा अपेक्षाओं को लागू करने के लिये राष्ट्रीय कंप्यूटरीकृत रिकार्ड सुरक्षा दस्तावेजों को तीन महीने की अवधि के भीतर तैयार किया जायेगा ।
101. साइबर कोष की भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय - स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी गठित की जायेगी । सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर "डॉटा" भूमिगण्डन सचिवालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और रासूविकेन्द्र के प्रतिनिधियों और नासकॉम के प्रतिनिधियों से एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी प्रतिष्ठापित की जायेगी जोकि निगरानी अवसंरचना (जोकि अधिकतर मामलों में आई एस पी द्वारा वित्त पोषित किये जायेंगे) और लाइसेंस करारों में व्यायोग्य खण्डों को सम्मिलित करने के लिए इस क्षेत्र में संज्ञार निगरानी के तकनीकी पहलुओं का अवलोकन करेगी।
102. कंप्यूटरीकृत डॉटा के अनुरक्षण हेतु सूचना सुरक्षा, गोपनीयता और डॉटा संरक्षण अधिनियम पर एक राष्ट्रीय नीति को सरकार द्वारा 6 माह के अवधि की भीतर तैयार किया जायेगा ।
103. कानून, न्याय और कम्पनी कार्य मामलों के मंत्रालय द्वारा कानूनी संरचना के भीतर साइबर व्यातिक्रम के कार्यकलाप संबोधित किये जायेंगे ।

104. रक्षा संस्थानों द्वारा विकसित अनुभव और किप्टोलॉजी और साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी को देश में व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु नागरिक सूचना सुरक्षा एजेंसियों को पर्याप्त रूप से इसे अन्तर्गुह्य किया जायेगा जिससे कि ई एफ टी, डिजिटल हस्ताक्षर आदि का बड़े स्तर पर सुरक्षित रूप में इस्तेमाल किया जा सके और सूचना सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा में वृद्धि की जा सके ।
105. निजी और सार्वजनिक एस टी पी केन्द्रों में कागजात के रूप में रिकॉर्ड रखने की पद्धति को दो माह की अधिकतम अवधि तक प्रतिबंधित किया जायेगा, जिसके पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक/मैग्नेटिक/ऑप्टिकल मीडिया में ही रखा जायेगा ।
106. इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1993 और इंडियन पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1888, इंडियन टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को रोजमर्रा के जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जायेगा । आवश्यकता पड़ने पर अन्य कानूनों/अधिनियमों में पर्याप्त परिवर्तन भी किये जायेंगे ।
107. सदियों की समिति द्वारा गठित साइबर कानून समिति द्वारा तैयार किये गये साइबर कानून के ड्राफ्ट सेट को प्रथम चरण के रूप में सरकार द्वारा 6 माह के भीतर उपयुक्त संशोधन करने हुए और उसे कार्यान्वित करने हुए अनुमोदित किया जायेगा ।
108. पद्धतियों/कानूनी कार्यकलापों के संबंध में सभी आवश्यक अनुदेश, अधिसूचनाएँ और संशोधनों को संबंध मंत्रालयों/विभागों द्वारा न्यूनतम आवश्यक समय सीमा में जारी किया जायेगा । डॉट के मामले में इसमें टी आर ए आई के साथ परामर्श की समयावधि शामिल होगी । डी ए आर एण्ड पी जी और एम ओ एल कार्यदल द्वारा समक्ष लाये गये सभी कानूनी मुद्दों पर कानूनी प्रारूप की सिफारिश करेगा और सभी बयानों की जाँच करेगा । मानव संसाधन मंत्रालय पर एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी संशुद्धियों (58) से (75) तक में सामने लायी गयी प्रत्येक गतिविधि हेतु एक समयावधि को सुनिश्चित करेगी और इस संबंध में प्राथमिकताओं को तय करेगी ।

PLANNING COMMISSION  
RESOLUTION  
New Delhi, the 25th July, 1998

No. IT-TF/5/98 - Government of India, recognising the impressive growth the country has achieved since the mid-Eighties in Information Technology is still a small proportion of the potential to achieve, has resolved to make India a Global IT Superpower and a front-runner in the age of Information Revolution. The Government of India considers Information Technology (IT) as an agent of transformation of every facet of human life which will bring about a knowledge based society in the twenty-first century. As a first step in that direction, the President of India orders, with immediate effect, the following revisions and additions to the existing Policy and Procedures for removing bottlenecks and achieving such a pre-eminent status for India:

- (i) The 108 recommendations of the Information Technology Action Plan, submitted by the National Task Force on Information Technology and Software Development set up vide Prime Minister's Office Notification No.F.No. 360/31/C/10/98-ES.II dated 22-5-1998, as given in the Annexure, be notified by all the concerned Ministries/Departments of the Government of India and necessary instructions and amendments to the Procedures/Law be issued expeditiously fully reflecting the spirit of the recommendations.
- (ii) Towards the attainment of the inspiring mission placed by the Prime Minister before the nation to make India an Infotech superpower in the shortest period of time, an effective awareness building campaign shall be launched for the removal of all infrastructural bottlenecks and creation of a nation-wide IT culture.

N. SESHAGIRI, Spl. Secy.

**ANNEXURE**

- (1) INTERNET access nodes will be opened by DoT and authorised ISPs at all District Headquarters and local charging areas by 26th January 2000. As an interim measure, and till nodes are provided in all local charging areas, access to nearest INTERNET access nodes will be on local call rates, progressively with effect from 15th August 1998. ISPs will be responsible for ensuring that this facility is not misused for telephone traffic.

- (2) Voice & Data Communication is permitted for IT Software Development and IT Services on dedicated or leased circuits, but no telephone traffic is permitted. Surcharge on 64 Kbps and higher capacity circuits for voice-cum-data applications is withdrawn with effect from 15th August 1998.
- (3) Doubling of the lease rental charged by DOT for high speed data circuits leased by Closed User Group (CUG), Licensees of Basic Service, Cellular Service and other Value Added Services and users shall be reduced to single normal lease rental charge.
- (4) Requests made by public sector Software Technology Park (STPs) or Private Sector STPs or IT promotional organisations approved by the Government for release of bandwidth shall be acted upon by the VSNL by intimating INTELSAT within two weeks of receipt. Software Technology Park of India (STPI) and Government network Service Providers shall be given a status of Direct Access Provider Category III to enable them to send their bandwidth requirements directly to INTELSAT.
- (5) Setting up of Central call centres by IT Service Providers shall be permitted for which DOT and other Basic telecom Service Providers will make available bandwidth.
- (6) Intelligent Network (IN) Services including free phone and premium Service (e.g. 1-800 and 1-900) shall be introduced by DoT by 31 December 1998 in several cities.
- (7) For setting up ISP Operations by companies, there shall be no license fee for the first five years and after five years a nominal license fee of one rupee will be charged.
- (8) The monopoly of the VSNL on International Gateway for INTERNET shall be withdrawn and authorised public/government organisations will be allowed to provide INTERNET Gateway access including international leased circuits directly without going through VSNL Gateways. Private ISPs are allowed to provide such Gateways after obtaining Security clearances for which the Interface of Private ISPs shall only be with DOT, which will set up a mechanism for obtaining security clearance from different security agencies.

- (9) It should be made free for the Railways, State Electricity Boards and National Power Grid Corporation, to lease the excess/spare capacity for data transmission to DOT or licenses of DOT for the basic as well as value added services or to any other users including Internet Service Providers in conformity with the license conditions, where applicable.
- (10) DOT shall allow interconnectivity of the Government Data Networks and Closed User Group(CUG) Networks for data transmission. For other networks, inter-connectivity policy shall be worked out by DOT and the Task Force within one month.
- (11) Providing access to INTERNET through authorised Cable TV shall be permitted to any service provider without additional licensing subject to applicable Cable Laws.
- (12) The 'last mile' linkages shall be freely permitted either by fibre optic or radio communication for IT application enterprises, IT promotional organisations and ISPs. In case of radio linkages, coordination by the Wireless Adviser will be observed to avoid frequency interference.
- (13) The radio frequency band in the range of 2.400 - 2.4835 GHz is open for exploitation for last mile connectivity as per published siting criterion followed by SACFA by any government organisation or PSU or Private Sector Company to set up Spread Spectrum based non-interface type Wireless equipment subject to a maximum of 4 Watt EIRP and a maximum channel spread of 10 MHz. WPC will periodically issue a district-wise directory of two or three selected bands of 10 MHz each for each of the districts on the criteria of least congestion. The use of the band is on the basis of non-interference, non-protection and non-exclusiveness; Private Sector, Public Sector and Government operators shall apply to DOT and obtain registration and licence from WPC. DOT will set up an internal mechanism to obtain security clearance, which would be obtained in a maximum period of 45 days. The operators would provide such facilities as are stipulated for monitoring purposes. WPC would be empowered to monitor the violation of conditions stipulated and impose penalties on defaulters in three stages: Written warning, monetary penalty and debarring for two years. Technical Audit Unit comprising a representative each from the Defence, DOT, DOE, NIC and from NASSCOM for the limited purpose of representing private user interests), and chaired by the Secretary, DOT shall monitor the implementation of the above policy

- (14) Data communication requirements for Electronic Commerce(EC/EDI) shall be met by DoT in a liberal framework by assigning the highest priority under their priority classification if the EC/EDI requirement is certified by authorities in Government authorised by the Ministry of Commerce.
- (15) Public TeleInfo Centres (PTIC) having multimedia capability specially ISDN Services, Remote Database Access, Government and Community Information systems, Market Information, Desk Top Videoconferencing, TeleInfo and INTERNET/Web Access Services shall be permitted and encouraged by the Government. DoT and other Basic Service Providers, Value Added Service Providers and authorised IT promotional organisations shall be permitted to promote these services on non-exclusive basis. No license fee will be charged for operating these services and the usual tariff, where applicable, will be payable by the PTIC Service providers/franchisees. Efforts will be made by DoT and other Service Providers to upgrade STD/ISD PCOs to convert them into these powerful PTICs for which ISDN or other digital facilities shall be provided on priority without necessarily having to make additional investment on this account.
- (16) DOT shall take suitable action to delicense Multimedia services, including FAX, provided by PCOs.
- (17) To enhance the pace of PC and INTERNET penetration in remote and far flung areas in the country, the policy should enable the Defence Services to provide connectivity to their communication systems for civilian applications after due examination.
- (18) Existing Software Centres by themselves may not be able to fulfill the high targets now set for the IT industry by the year 2008. International experience has shown that hi-tech industries flourish essentially in the rural hinterland adjacent to cities with modern telecom and communication infrastructure and top class hi-tech educational/research institutions. India will promote such 'Hi-tech Habitats' in the rural hinterland adjacent to suitable cities. For this purpose suitable autonomous structures will be designed and progressive regulations will be framed to facilitate infrastructurally self-contained self-financed Hi-Tech Habitats of high quality. Initially, five such Hi-Tech Habitats shall be planned and implemented in the rural hinterland of the cities: Bangalore, Hyderabad, Pune, Delhi and Bhubaneswar. It is estimated that progressively 50 such Hi-Tech Habitats can be viably set up by empowering the State Governments to autonomously nucleate them within a technologically progressive and

administratively liberal set of guidelines to be prepared by a special Working Group on Hi-Tech IT Habitats to be set up by the Task Force.

- (19) (a) Definition: *"IT Software" means any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code, recorded in a machine readable form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine falling under heading 'IT Products', but does not include 'non-IT products'. 'IT service' is defined as any service which results from the use of any IT software over a system of IT products for realising value addition. The term 'IT Industry' shall cover development, production and services related to IT Products. The term 'IT Software' shall be substituted in place of 'Computer Software' in all notifications.*
- (b) Finance Ministry (CBEC) shall introduce a new classification called, 'Information Technology (IT) Products' including Computer, Digital/Data communication and Digital/Data Broadcasting products, by recognising the progressive technological convergence of these three categories including all items in the classification list in Attachment A (Section I and Section II) of the WTO (ITA) Agreement and, additionally, Data Communication equipment.
- (c) IT Software shall be entitled for zero customs duty and zero excise duty.
- (20) A revised Notification giving the following new schedule for the Government of India acceding to the WTO-ITA Ministerial Declaration of 13 December 1996 at Singapore shall be issued by the Ministry of Finance:

In Attachment A, Section I and II of WTO-ITA:

- (a) Duty shall be brought down to zero by 1 January 1999 on the following items: Parts & components excluding populated PCBs in HSN 8473.30, all storage devices in HSN 8471.70, ICs above Rs. 1000 in HSN 8542, Stepper Motors in HSN 8501.10, Colour Graphic Display Tube in HSN 8540.40 and Deflective components for Colour monitor in HSN 8504.
- (b) Out of the 217 items listed in ITA-I, 94 items which were proposed earlier for zero duty by 1st January 2000 shall now be advanced to 1st January 1999.

- (c) The remaining items earlier proposed for zero duty by the 1st January 2003/2004/2005 shall now be advanced to 1 January 2002.

Concomitantly, the following schedule will be adopted:

- (d) • Duty on Capital Goods for the manufacture of items in (c), wherever applicable, becomes zero by 1 January 2000.
- Inputs/raw materials for the manufacture of the items in (c), wherever applicable, becomes zero by 1 January 2001
- Dual purpose items will be taken care of, wherever applicable, by allowing duty drawback benefits or by treating the supplies to the IT industry as deemed export.

Zero excise duty is concomitant with zero Customs duty with in-phase reduction.

Additionally, other suitable supportive measures shall be taken to encourage Indian hardware industry to become globally competitive in the light of the revised WTO-ITA schedule.

- (21) Customs duty on import of CD-ROMs or Optical Disc Media or Magnetic Media containing text, data or multimedia as content shall be charged only on the media and not on the contents.
- (22) Imported IT Products shall be permitted to be taken out of bonded offices or out of Electronics/IT Units under EOU/EPZ/STP/EHTP Schemes after a period of 2 years from the date of import if these are donated to recognised educational institutions, Government organisations and registered charitable hospitals, etc., as defined in the Clause 9.19 of the Handbook of Procedures (Volume I) of the EXIM Policy through a customs notification.
- (23) IT Software and IT Services companies, being constituents of the knowledge industry, shall be exempted from inspection by Inspectors like those for Factory, Boiler, Excise, Labour, Pollution/Environment etc.,

- (24) With technological advancements in Wide Area Computer-Communication networks, which have brought about 'Virtual Technology Parks' in which IT Software and IT services are developed through online integration of software and services subsystems from widely separated locations in the country, the concept of physical bonding has become obsolete. Accordingly, Software developers/exporters are exempted from Customs bonding at various export

promotion schemes including STP/EOU/EPZ, etc. The export obligation shall be the same value as given under the EPCG Scheme. Existing bonded units under the various Software Export Promotion schemes will also be considered under the above scheme.

- (25) A clarification shall be issued by CBEC that Service Tax is not applicable on computer software development industry.

- (26) The Ministry of Civil Aviation shall issue the following notifications/ amendments in the regulations :

- Export shipment time for air cargo will be reduced to less than 24 hours.
- "Known Shipper" will be introduced to avoid delays on account of cooling off period.
- Cargo companies and other associated agencies to allow consolidation of export air cargo.

- (27) Section 80 HHE of the Income Tax Act provides for income tax exemption to profits derived from software and services exports. This section shall be amended as follows:

- The existing formula will be so changed that tax on profits shall not have any relation to domestic turnover.
- The definition of software and export turnover will be changed so as to include IT services exports.
- The benefits of this Section for income tax exemption to profits from exports will be extended to supporting IT Software & IT Services developers .

- (28) IT software and IT services shall be deemed as manufacturing activity for the limited purpose of applicability of Section 10 (15) (iv) of the Income Tax Act.
- (29) IT Software and IT Services shall be exempted from withholding tax through amendments in the 'explanation' of Section 9 of the Income Tax Act.
- (30) No gift tax shall be charged for the giver or Income Tax for the receiver on PCs upto Rs. 50,000 of the original purchase price.
- (31) For any investment made in IT products and IT software 100 % depreciation shall be allowed in two years for which Ministry of Finance shall take suitable action.
- (32) As the traditional method of asset-based funding of working capital would not meet the adequate and timely requirements of fund of the software sector, a differential and flexible approach shall be adopted by giving special dispensation towards working capital requirements of this sector in view of the unique nature of the industry. Accordingly, RBI shall issue, by 15th August 1998, new guidelines with regard to working capital requirements for the IT software and services sector which would be based on simple criteria such as turnover. Banks shall be advised to give 25 percent of the contract value for 18 months, with the first six months as term loan (without collaterals) and from the 7th month onwards annualized Cash Flow Statements shall be accepted instead of collaterals.
- (33) IT software and services industry shall be treated as a Priority Sector by banks for the next five years. This would help to meet the requirements of IT software and services exports, and also the IT industry and applications within the country. Major banks will be advised to create specialised IT financing cells in important branches, where IT Software and Services units are sufficiently large in number. Performance in this dimension will be monitored by the Ministry of Finance.
- (34) Against the present estimate of Rs. 400 crores of working capital for the industry, the amount shall be increased to around Rs. 1200 crores by the year 2000 subject to the broad criteria of pro-rata increase for the prospective requirements 24 months ahead as compared to the actuals of the current requirements at any given time. A system will be put in place which would enable substantial increase in working capital provided by the banks.

- (35) Bank lending to IT Software and Services exporters shall be made eligible for RBI refinancing with sufficiently low interest rates.
- (36) The banks shall be allowed to invest in the form of equity in dedicated venture capital funds meant for IT industry as part of the 5 percent of increment in deposits currently allowed for shares.
- (37) Banks/FIs like ICICI, IDBI, UTI and SBI shall set up joint ventures with Indian or foreign companies for setting up of at least four different venture capital dedicated funds of a corpus of not less than Rs. 50 crores each to cater to the credit need of the industry.
- (38) Venture capitalists shall be allowed to set off losses in one invested company and profit in another invested company during the block of years for the purpose of income tax.
- (39) For Sweat Equity, an additional new proviso shall be added to Clauses 73 and 74(7)(6) of Companies Bill, 1997: 'The Computer Software Companies in India or their subsidiaries abroad may also issue Sweat Equity to their Promoter-Directors or whole time Directors or employees for providing any know-how, intellectual property or value addition to the Company on exclusive basis on such terms and conditions as may be prescribed by SEBI or the Central Government as the case may be.' A new definition No. (66) will be added after definition No. (65) in Clause 2 as under as "(66) Sweat Equity means equity allotted to promoter-Directors, whole time Directors or employees for providing any know-how intellectual property or value addition to the Company".

Amendments shall also be made in the Company Law to provide for buy-back of shares as well as differential pricing of shares.

- (40) Ministry of Finance shall include IT software and IT service sector while issuing general guidelines for dual listing of companies, as well as while considering two-way fungability for ADRs/GDRs.
- (41) • Dollar Linked Stock Options to employees of Indian Software companies were announced in the 1998 Budget and detailed guidelines on this have been issued by DEA, Ministry of Finance. This shall be modified in accordance with the definition of IT Software and IT Services given under (19)(a) and (b) above.

- Employee Stock option schemes for stock listed in India would also be encouraged. Also, clarification shall be issued that income tax is applicable only at the time of sale and not at the time of exercise of option.

(42) Recognising the high velocity of business, high degree of competition and fast technological obsolescence faced by the IT software and IT service exporters, RBI shall set up an Inter-Institutional Group(IIG) which will make recommendations within one month to maximally accommodate the following recommendations:

- (a) A blanket approval for overseas investment for acquisition of software/IT companies across the board for software exporters with previous three years cumulative actual export realisation in excess of US \$ 25 million to be given up to 50 % or US \$ 25 million, whichever is lower, out of the cumulative actual export earning of the previous three years. This is subject to submission of a certificate of software industry by appropriate authorities.
- (b) For FERA approvals beyond this limit, RBI would set up a mechanism for expeditious processing of applications from this sector. This shall be announced by 15 August 1998.
- (c) For overseas ventures, a dispensation shall be given for allowing the capitalisation of both goods and services; RBI shall accordingly notify this in consultation with Commerce Ministry by 15 August 1998.
- (d) As the present allowable limit of 70% of the contract amount for expenditure abroad does not provide flexibility for utilisation for the purpose of general corporate objectives or for business growth purposes, RBI shall permit IT exporters to freely spend upto 5% of the export proceeds abroad (out of the total 70%) for miscellaneous/sundry purposes to give full flexibility. Also, a new list of allowable expenses under the 70% limit would be worked out .
- (e) RBI shall issue revised EEFC guidelines to eliminate restrictions on staggered remittance, second and higher generation subsidiaries and also to allow 20% of the EEFC balances for the use on the following:
  - i) Advance remittances for downloading software (upto US \$ 1 lakh per transaction).

- ii) Purchase of equipment and related expenditure
  - iii) Miscellaneous expenses not detailed in EEFC guidelines (upto 5% ) of EEFC balances. Such EEFC accounts shall be permitted for making payments from offshore branches of Indian banks directly.
- (f) Use of International Credit Cards (ICC) abroad for a variety of purposes required by the IT Software and IT Services sector shall be permitted, the detailing of which will be carried out by RBI and notified by 15 August 1998, in particular:
- i) All payments currently made under Exchange Earnings Foreign Currency (EEFC) Account shall also be allowed to made through International Credit Cards (ICC). Advance payment for IT software and IT services shall be permitted to be done through ICC for which RBI will issue a notification. Notification shall be issued that ICC may also be used for paying for IT Software and IT services purchased over INTERNET or EXTRANET and also for registering domain names.
  - ii) RBI shall issue a modified and simplified SOFTEX form required for IT Software and IT Services export by 15 August 1998.
- (43) In the EPCG scheme a system of self-declaration shall be introduced with 100% post-checking subject to punitive penalty for default.
- (44) The value limit for import of IT Products including personal computers shall be reduced from Rs. 1.50 lakhs (c.i.f) to Rs. 70,000 (c.i.f).
- (45) Private and public organisations providing IT infrastructure shall be included for duty exemption for importing capital goods. Such service providers, in view of such capital goods imported, shall undertake the export obligations as provided for import of capital goods in the EPCG Scheme.
- (46) The India Brand Equity Fund Scheme operated by the Ministry of Commerce shall be made available for Software companies with lower interest and longer interval

- (47) On-site IT Services should be made easier by combating Visa regulations of the recipient countries through a planned diplomatic strategy by the Ministry of External Affairs and the Indian Missions abroad for which MEA will create a suitable dedicated structure. This will also include signing of totalisation agreements, wherever necessary so as to maintain the competitive advantage of Indian companies.
- (48) Returns from package software development shall be increased by enabling Indian Marketing companies to set up wholesale companies abroad. They shall also be given maximum flexibility in organising the marketing of package software from India through INTERNET.
- (49) For benchmarking our country with our emerging competitors, a study shall be conducted at Government cost once in two years by internationally reputed consultancy companies.
- (50) Restrictions on the location of IT software and IT Services (including IT training) companies in residential areas shall be removed.
- (51) To enable organisations and companies to identify, explore and plan strategies for Large Niche Markets like Y2K and Euro, nationally and corporate wise, all applicable provisions shall be made applicable on higher priority basis. Through MOC and DOE funds 'India Pavilions' shall be set up in several major IT exhibitions around the world through the initiative and coordination of ESC and NASSCOM.
- (52) Recognising the catastrophic effect of the Y2K problem for solving which a few hundred billion dollars are being spent around the world, an immediate investment of Rs. 700 crore as corpus funds shall be mobilised to control the crisis in critical Government, Public and Private organisations and services: efforts to sensitise such organisations in the country facing the crisis shall be taken up by the Government immediately including issuance of Government orders for strict compliance in a time bound manner; a High level empowered Task Force with representatives from the Government, Industry Associations, Banks and Financial Institutions, Defence Services, Utility and other Public Service organisations, Railways, among others, shall be constituted by the Government of India.

- (53) • 'Mega Web sites' shall be created on INTERNET for promoting marketing and encouraging Indian Software products and packages under multiple initiatives.
- Creation and hosting of websites on servers located in India will be encouraged.
- (54) Under DEPB Rupee trade arrangement, IT Software, IT Services and IT product export to Russia shall be permitted with promotional support given by the Electronics and Software Export Promotion Council (ESC), STP, etc.
- (55) All promotional and liberalisation policy instruments available to IT Software and IT Services shall be made available to IT enabled services including the Information Content Industry by classifying IT enabled Services as tantamount to IT Software and IT Services.
- (56) For promoting Indian Software Packages (system as well as application software) users shall be given fiscal incentives for buying Indian packages. A special screening mechanism will be worked out for identifying the more promising packages developed in India and giving consistent support by the Government as well as the industry for ensuring acceptance in international markets.
- (57) Private STPs shall be encouraged to be set up by combining the provisions under (4), (7), (8), (12), (13), (24), (43), (45), (54) and (55), among others.
- (58) The Government shall soon launch three schemes -- Vidyarthi Computer Scheme, Shikshak Computer Scheme and School Computer Scheme -- to enable students, teachers or schools respectively desirous of buying computers to do so under attractive financial packages. These schemes will be supported by a suite of initiatives such as lowering the cost of PCs, easy-installment bank loans, computer donations by IT companies and other business houses, bulk donations of computers by NRI organisations, large-volume bargain price imports, multi-lateral funding, etc.
- (59) Computers and Internet shall be made accessible to schools, polytechnics, colleges, and public hospitals in the country by the year 2003.

- (60) All universities, engineering colleges, medical colleges and other institutions of higher learning in the country as well as Research and Development Organisations shall be networked for a supplementary programme of distance education for improving the quality of education before year 2000.
- (61) The seven national level institutions (IITs, IISc.) shall be encouraged to triple their output of students in IT by suitably restructuring the programme. In addition, the soft-cap project approved by the Committee of Secretaries shall be implemented with the Ninth Five Year Plan commitment of Rs.300 crores.
- (62) A National Council of IT Education, as a part of the AICTE, comprising experts from both the industry and the academia, shall be set up for defining courses and their content in the light of rapid developments taking place in Information Technology. The Council will also initiate a 'Teach the Teachers' (3T) programme for upgrading on a regular basis the IT knowledge and skills of teachers.
- (63) An IT Course Module shall be made a compulsory component of all Degree Courses within a short period.
- (64) The setting up of Indian Institutes of Information Technology (IIIT) shall be implemented with urgency to make up for the lost time. Hi-tech institutions like the Indian Institute of Information Technology (IIIT) will be given the status of a University by statute.
- (65) The Government shall promote the pairing of our Universities with centres of excellence in IT in developed countries.
- (66) Specific courses shall be launched in association with the Software Industry and IIMs to provide Project Management skills and develop specialised courses on Software Marketing.
- (67) The concept of SMART Schools where the emphasis is not only on Information Technology in Schools, but also on the use of skills and values that will be important in the next millennium, shall be started on a pilot demonstrative basis in each State.
- (68) An Institute for Computer Professionals of India shall be set up on the pattern of the Institute of Chartered Accountants of India; the Institute will be nucleated by NASSCOM with initial financial support from the industry and the

Government. The Institute will be given the responsibility as an Accreditation Body for IT Education and Training Programmes with full Government recognition in addition to the DOEACC Programme of the Department of Electronics

- (69) To enhance the knowledge base of IT related education at all levels the Government shall establish Information Technology, System Engineering and IT Security Institutes from within existing manpower of the Armed Forces. The Centres of Excellence in IT Software and System Engineering in the Defence Services will be utilised to the national advantage.
- (70) Virtual Institutes in different parts of the country shall be set up to achieve excellence in distance education.
- (71) The talent and expertise of IT-trained ex-servicemen shall be utilised for IT penetration in rural India and Government will fully support this offer of the Armed Forces. A Plan will be prepared and implemented for utilising the services of the large number of IT literate defence personnel retiring every year for propagating the IT culture at sub-district levels.
- (72) A 'National Qualification Framework' shall be established for computerised online objective system of knowledge acquisition; An 'Educational Credit Bank' shall be implemented for giving flexibility to integrate credits earned in different institutions/systems towards the eligibility for diplomas and degrees.
- (73) A Specialised committee shall be formed to coordinate the setting up of National and State level Digital Libraries Projects.
- (74) A pilot project shall be launched in some lead districts which have already attained universal literacy, with the aim of achieving universal computer literacy in all the secondary schools in these districts. Alongside, the network of educational institutions in these districts will be assisted to maximise the induction of IT in order to create world-class talent at the top-end of the education pyramid. These pilot projects will be joint initiatives of the local educational institutions, respective State Governments and the Centre. In the first instance, such a pilot project will be launched in Dakshin Kannada and Udupi Districts in Karnataka on a substantive self-financing basis. Within a short time, the same will be extended to suitable districts in other States.

- (75) In view of the lower-than-national-average levels of technical and IT education facilities in Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh Rajasthan and North-Eastern States, several educational centres will be identified with a view to making them models for IT-based education and training at all levels. The aim of this initiative will be to promote IT education and awareness in all the fields of knowledge and knowledge-based enterprises. Allahabad shall be developed as the first such model IT-based education-cum-business centres. Within a short time, this initiative will be extended to other States which are underdeveloped in IT.
- (76) Government shall encourage the setting up of value-added network services including ATMs, Electronic Kiosks, Telephones, Smart Cards, etc., for providing a 'One-Stop Non-Stop' service to the public.
- (77) To make IT a mass movement, an awareness creation strategy shall be worked out within two months and the structures for implementing the same shall be put in place.
- (78) A major promotional campaign shall soon be launched to boost IT in Indian languages. This campaign will be based on a multi-pronged approach, involving fiscal and other incentives for R&D, production, marketing and popularisation of IT products in Indian languages. This recommendation addresses the reality that India can become a major IT power only if IT penetration in the country deepens and widens-which in turn, is dependent on large-scale use of IT in Indian languages.
- (79) The Government shall take all the necessary steps to boost IT for agricultural and integrated rural development. Towards this end, a number of demonstration projects will be devised in each State taking into account the specific strengths and needs at the local level. A unique 'WIRED VILLAGES' pilot project has been launched at the Warananagar Cooperative Complex in Kolhapur District in Maharashtra. Efforts will be made to quickly replicate such projects in other states.
- (80) The Government shall take necessary measures to develop, productivise and use, in domestic and global markets, indigenous technologies in wireless telecommunication to achieve the national objective of rapid, low-cost expansion of telephone and Internet connectivity in rural and remote areas. Similarly, promotional measures shall be taken to encourage technologies that bring IT and Internet to the masses through the vast network of Cable TV houses.

- (81) For promoting electronic commerce in a time-bound manner, a strict directive shall be given to Sea Ports, Airports Authority of India, DGFT, Banks, Container Services, Customs and Indian Railways in accordance with the programme approved in the tenth Export Promotion Board meeting.
- (82) Bar Coding of every item sold in the country shall be made compulsory within a five-year period.
- (83) The Armed Forces shall integrate far-flung and remote areas (Ladakh, North-East, Andaman & Nicobar Islands, Kutch, Lakshadweep and Minicoy Islands, border areas of Himachal and Rajasthan) with mainstream India, through IT penetration as part of their Civic Action Programme. The funds for this initiative shall be provided through the Government/Venture/Seed Capital.
- (84) The Cabinet has approved NIC's proposal to make government Information, other than that having a bearing on security, available to the public. This decision shall be implemented by suitably empowering NIC to do so. This recommendation addresses the felt need for easy availability and extensive transparency of government information.
- (85) District Information System (DISNIC) Plan Programme shall be made widespread and databases updated online, shall be made available to the public and Panchayats, among others. Courts Information System(COURTIS), Parliament Information System (PARLIS), Computerised Rural Information System Programme (CRISP) and other such databases shall be updated online over NICNET and access to public facilitated .
- (86) A Citizens Charter for effective and responsive administration in terms of time-bound service to the public shall be framed and implemented under the coordination of the Department of Administrative Reforms & Public Grievances and hoisted on the official INTERNET Web Site 'India Image' of the Government of India. The DOP & T shall examine all the issues relating to citizen-IT interface.
- (87) Each Department/Agency in the Central Government and State Governments shall be required to prepare a Five Year IT Plan.
- (88) 1-3% of the budget of every Ministry/Department shall be earmarked for applying IT in the Department/sector; this investment will include not only the purchase of IT products, IT Software, but also for training and IT services; Reappropriation of the Department's budget for the IT sub-budget head shall be within the delegated powers of the Head of the Department.

- (89) NIC, at the national level, and technology service organisations at the State level, shall establish 'Framework Contracts', on a non-exclusive basis, with reputed suppliers to provide a wide range of IT consultancy, specialist services and IT products to Government agencies to reach the benefit of lower costs through bulk purchases.
- (90) India shall participate in international projects like 'Government Online' Project of G-8 countries so as to not only learn from the experience of others but also to contribute to the global experience in planning and implementing projects to promote IT in Government.
- (91) Tele-commuting is recognised as a new modality of doing work in an office and labour laws accommodating the same shall be enacted. An option shall be given to employees, where feasible and efficient, to accomplish part of their work through telecommuting in the framework of 'Management by Objectives' (MBO).
- (92) The Government of India shall set up a central repository of data elements in Government with the NIC and make it accessible through NICNET.
- (93) The recommendations of the TG-MAP Committee for Map and GIS Data Policy approved by the Committee of Secretaries under the Cabinet Secretary, shall be notified by the Ministry of Defence expeditiously.
- (94) A computerised National Inventory of Training pertaining to different areas shall be maintained.
- (95) A computerised Inventory of Government best practices for electronic access shall be maintained.
- (96) Government shall stipulate IT literacy as an essential requirement for all future Government and public sector employment; in the Annual Confidential Reports of government employees, a column shall be introduced regarding contribution to IT utilisation in the department/organisation.
- (97) A National Institute of Smart Government shall be set up to focus on all issues concerning IT-supported governance.
- (98) State Institutes of Public Administrations shall be re-engineered to help bring about IT-responsive State Governments.

- (99) Suitable floor space in Government buildings, which are not utilised during non-office hours, could be given to private educational institutions for IT training purposes in return for a proportionate number of free nominations of Government employees for IT training.
- (100) A National Computerised Records Security Document shall be prepared within three months for enforcing security requirements by consulting similar documents prepared by SAG, JCB, WESEE, etc.
- (101) An Information Security Agency shall be set up at the National level to play the role of Cyber Cop. On security related issues an Inter-Ministerial Committee shall be set up consisting of the representatives of DOT, Cabinet Secretariat, MHA, MOD, DOE and NIC and representatives from NASSCOM to look into the technical aspects of monitoring of communications in this sector (including Internet) to enable the setting up of the monitoring infrastructure (which in many cases would have to be funded by the ISPs) and incorporation of suitable clauses in the licence agreements.
- (102) A National Policy on Information Security, Privacy and Data Protection Act for handling of computerised data shall be framed by the Government within six months.
- (103) Cyber infractions shall be addressed within the legal framework by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs.
- (104) The cryptology and Cyber Security knowledge and experience developed by the Defence establishments shall be suitably transferred to the civilian information security agencies for wider dissemination in the country to increase information security, network security and bring about a greater degree of secure use of EFT, Digital Signature, etc.
- (105) The procedure of keeping records in paper form in public and private STPs shall be restricted to a maximum duration of two months after which the records shall be kept only in the Electronic/Magnetic/Optical media.
- (106) The Indian Telegraph Act of 1885, the Indian Post Office Act of 1888 and the Indian Wireless Telegraphy Act of 1993 shall be suitably modified in the light of the growing predominance of IT in day-to-day life. Suitable changes will also be made in other Laws/Acts, wherever necessary.

- (107) The draft set of Cyber Laws prepared by the Cyber Law Committee set up by the Committee of Secretaries, shall be approved by the Government with suitable modifications and implemented, as a first step, within six months.
- (108) All necessary instructions, notifications and amendements to procedures/Law shall be issued by the respective Ministries/Departments in the minimum essential time. In the case of DOT this shall include the period of Consultation with TRAI. The DAR&PG and MOL shall examine the details and recommend draft legislation on all the legal issues(including amendmentss of the Acts) identified by the Task Force. An Inter-Ministerial Committee in the HRD Ministry shall prioritise and determine a time frame for each activity identified in recommendations (58) to (75).